प्रसंगशः

आलोक मेहता

हथियारों की खरीद में नं.-1

दुनिया में बेचने-खरीदने वाले बहुत हैं और अमेरिकी नकेल से टकराव बढ़ रहा है

मणिशंकर अय्यर की स्पष्टवादिता पर नाराज होने का कोई कारण नहीं है। वह भारत सरकार के सम्मानित पंचायत और खेल मंत्री हैं। गांवों और जमीन की असलियत उनसे अच्छी कौन समझ सकता है। जीर्ण-शीर्ण गांवों की दशा सुधारने के लिए उन्होंने अपने राजनयिक अनुभव का लाभ उठाते हुए साधन-संपन्न नार्वे के युवराज के समक्ष खुलकर कह दिया कि 'हम तो कटोरा फैलाकर आपसे सहायता मांगेंगे क्योंकि गरीब-जर्जर गांवों की हालत सुधारनी है।' भीख के इस विनम्र अनुरोध पर प्रतिपक्ष के ही नहीं, सत्तारूढ़ नेताओं को भी थोड़ा बुरा लगा। भारत की आन-शान में मीठे शब्दों में भी तौहीन कैसे बर्दाश्त हो सकती है? फिर हिंदू ध्वजाधारी जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा या अरुण जेटली हों अथवा तिरंगे के साथ लाल झंडा थामे प्रणव मुखर्जी या चिदंबरम हों। छह वर्षों से राम-रावण की तस्वीर चिपकाए भाजपाई-वामपंथी तरक्की का राग सुना रहे थे, अब गांधी-लोहिया-मार्क्स का जुड़वां तमगा लगाए कांग्रेसी आर्थिक विकास दरों की धुन बांसुरी पर सुना रहे हैं। इस बीच अमेरिकी संसद ने बाकायदा बिगुल बजाकर रिपोर्ट जारी की है- 'कोई कुछ कहे, हथियार खरीदने वाले विकासशील देशों में भारत टॉप पर यानी नं.-1 है। पिछले साल 2005 में भारत ने कुल 5 अरब 40 करोड़ डॉलर (लगभग 230 अरब रुपयों) के हथियार खरीदने के सौदे किए। अपने आपको महाशक्ति समझने वाला चीन तक तीसरे नंबर पर है जो केवल 2 अरब 80 करोड़ डॉलर के हथियार खरीद पाया।' अमेरिकी रिपोर्ट में नहीं बताया गया है लेकिन महान भारत की उदार सरकार के महान नेता परदेस से आने वाले खास मेहमानों, राजनयिकों और सौदागरों को यह बताने में नहीं चूकते कि 2006 और 2007 में तो पिछले वर्षों की तुलना में कई गुना अधिक हथियार खरीदने की तैयारी है। ऐसी स्थिति में कटोरा फैलाने से थोड़ी किरकिरी स्वाभाविक है।

नेता किसी पार्टी के हों, उन्हें गरीबों को देखने या गरीबी दिखाने में बहुत तकलीफ होती है। वे भारत को शक्तिशाली परमाणु बमों से संपन्न, अत्याधुनिक हथियारों से सज्जित और जरूरत पड़ने पर अमेरिका-ब्रिटेन की तरह म्यांमार-सूडान जैसे किसी छोटे विकासशील देश को हथियार बेचने में सफल दिखाना चाहते हैं। फिर भले ही उन हथियारों का दुरुपयोग गरीब, भूखी जनता का दमन करने के लिए हो क्यों न हो रहा हो। इसलिए पहले अमेरिकी संसदीय अनुसंधान सेवा की रिपोर्ट में मिले सर्टिफिकेट और हथियारों की प्रतियोगिता में भारत की हैसियत की बात। सन 2005 में करीब 30 अरब डॉलर (1,350 अरब रुपयों) कीमत के हथियार बेचने वालों में रूस ने सबको पछाड़ा हुआ है। भारत सहित उसने दुनिया के विभिन्न देशों के साथ करीब 7 अरब डॉलर के हथियार बेचने के समझौते किए। दूसरे नं. पर फ्रांस और खरीद-फरोख्त का चतुर सौदागर अमेरिका तीसरे नंबर पर रहा है जिसने 6 अरब डॉलर के हथियार बेचने के समझौते पत्रों पर दस्तखत किए। संभव है, कुछ करोड़ डॉलर के सौदों में फिसड्डी रह जाने के कारण बुश से अमेरिका की हथियार कंपनियां थोड़ी खफा हो गई हों और इसी कारण संसद के चुनाव में उनकी रिपब्लिकन पार्टी को थपेड़े मिल रहे हों। अब भारत का ही सहारा है- परमाणु संयंत्रों के साथ हथियारों के बड़े सौदे करने पर शायद अगली रिपोर्ट आने तक उसकी हालत सुधर जाए। वैसे अमेरिकी संसदीय रिपोर्ट के अनुसार 1998 से 2005 के बीच हथियारों के बड़े आका अमेरिका ने 33 अरब 30 करोड़ डॉलर कीमत के हथियार विकासशील देशों को बेचे। जबकि रूस ने 21 अरब 80 करोड़ डॉलर कीमत के हथियार बेचने में सफलता पाई। मतलब दुनिया में होने वाले रक्षा सौदों का 60 प्रतिशत हिस्सा इन दो महाशक्तियों के पास है। उसमें भी असली नकेल अमेरिका के पास है। ताजा उदाहरण: चूहे से विकासशील देश वेनेजुएला ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका को थोड़ा सा कुतर दिया तो अमेरिका ने रूस के सुखोई विमान वेनेजुएला को दिए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया और उसकी वायु सेना के लड़ाकू विमान को अतिरिक्त कल-पुर्जों की सप्लाई भी रुकवा दी। सौदा कोई करे, रिंग मास्टर की भूमिका अमेरिका की रहती है। अमेरिका और संपन्न जी-8 समूह के अन्य विकसित देशों की छत्रछाया में ही विश्व की 85 शीर्षस्थ हथियार निर्माता कंपनियां सौदों और अस्त्रों को खपत में लगी रहती हैं। वैश्वीकरण के तहत उनके कारखाने चलते हैं और विकासशील या अति निर्धन अविकसित देशों में होने वाली सशस्त्र हिंसा के कारण हर वर्ष कम से कम तीन लाख निरपराध लोग मारे जाते हैं।

उदारीकरण या भगवाकरण अथवा लालीकरण के दौर में भारत की क्षमताओं में खासी बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्षों में सरकार अधिकृत रूप से कहने लगी है कि बड़े पैमाने पर हथियारों और कल-पुर्जों की खरीद के साथ भारत तकनीकी और उत्पादन क्षमता बढ़ाकर खुद हथियार बेचने में सक्षम हो रहा है। फ्रांस, इटली, रूस, इस्राइल जैसे देशों के साथ संयुक्त उपक्रमों के जरिये भारत दक्षिण-पूर्वी एशिया में हथियारों की बिक्री कर सफल निर्यातक की श्रेणी में गिने जाने का सपना संजोए हुए है। यों अमेरिका भी संबंधों के नए दौर में हथियारों की संयुक्त परियोजनाओं में भारत से साझेदारी चाहता है। इस तरह उसे अपने कारखानों के विस्तार में यूरोप की तरह उत्पादन के नए केंद्र स्थापित करने में भी आसानी होगी।

अमेरिका यह भी चिंता करता है कि रूस से भारत को अत्याधुनिक हथियार न मिलें। वह तर्क देता है कि ऐसा होने पर पाकिस्तान भी अत्याधुनिक हथियार जुटाएगा और दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ेगा। पर क्या हथियारों के सौदागर सच्चे दिल से भारत-पाकिस्तान में शांति और प्रगति चाहते हैं? यदि दोनों देश सारे विवाद और भीख के कटोरे कूड़ेदान में फेंककर विकास तथा गरीबों के उत्थान के अभियान में लग गए तो इनके हथियार खरीदने के भारी-भरकम बजट में कटौती नहीं होने लगेगी? वैसे अमेरिका की आंखों का सबसे बड़ा कांटा चीन भी इस धंधे में माहिर रहा है। सन 1980 के दशक में ईरान-इराक युद्ध के दौरान सस्ते हथियारों की बिक्री के बहाने चीन सफल अस्त्र निर्यातक बन गया। पिछले तीन वर्षों में उसका हथियारों का धंधा तिगुना हुआ है। पड़ोसी पाकिस्तान के लिए हथियारों के बड़े जखीरे के इंतजाम के अलावा ईरान, उत्तर कोरिया और कई अफ्रीकी तथा लातीनी अमेरिकी देशों को हथियार बेचने में चीन अग्रणी हो गया है। पाकिस्तान की उत्तरी कोरिया को चोरी-छिपे परमाणु हथियारों की टेक्नोलॉजी से संपन्न कराने में भूमिका संदिग्ध रही है। सबसे मजेदार स्थिति जर्मनी की है जो विश्व युद्ध की विभीषिकाओं से त्रस्त रहने के कारण परमाणु हथियारों के विरुद्ध चीख-पुकार मचाता रहा है लेकिन हाल के वर्षों में हथियारों के भंडार, उत्पादन और तीसरे देश के माध्यम से हथियारों के सौदों में अन्य यूरोपीय देशों से प्रतियोगिता करने लगा है। हथियार परमाणु हों या पारंपरिक, विनाशलीला तो उसी तरह करते हैं। पश्चिम यूरोपीय देश, अमेरिका, रूस, चीन जिन अफ्रीकी, पूर्वी एशियाई या लातीनी अमेरिकी देशों को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, वहां इतना धन गरीबों के लिए न्यूनतम सुविधाओं पर खर्च होने लगे तो विश्व समुदाय में सही अर्थों में शांति और खुशहाली दिखने लगे। लेकिन आंसू, भूख, खून की चिंता कितने देशों को है। विकासशील देशों को भारत से अवश्य बड़ी उम्मीदें रही हैं लेकिन अब तो वह भी शक्ति अर्जन के सौदों में नं.-1 हो रहा है और उसकी प्राथमिकताएं बदलती जा रही हैं। एक हाथ में कटोरा और दूसरे में बम रखते हुए विश्व शांति और निरस्त्रीकरण का चार्टर किताबों में चमकता रहेगा। ●